

01 मार्च, 2025
फाल्गुन, शुक्र पद्धति, दिवीया
संवत् 2081
पृष्ठ : 12, मूल्य : ₹3.00

रांची

शनिवार, वर्ष 10, अंक 132

* ओडिशा संस्करण

आजाद सिपाही



राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति से
उपचारात्मक स्वास्थ्य
सेवा के रूप में बड़ा
बदलाव आया है: नन्हा

FLORENCE	
GROUP OF INSTITUTIONS	
(A Unit of Haji Abdur Razzaq Educational Society)	
ADMISSION OPEN	
COLLEGE OF NURSING	
2 YEARS	M.Sc. Nursing
2 YEARS	Post Basic B.Sc. Nursing
3 YEARS	B.Sc. Nursing
2 YEARS	GNM (General Nursing And Midwifery)
2 YEARS	ANM (Auxiliary Nursing And Midwifery)
COLLEGE OF PARA MEDICAL SCIENCE	
4 YEARS	BM LT
4 YEARS	DMLT
2 YEARS	OT ASSISTANT
YEARS	ECG
2 YEARS	OPHTHALMIC ASST.
2 YEARS	Critical Care (ICU)
1 YEARS	RADIO-IMAGING
1 YEARS	ANESTHESIA TECH.
1 YEARS	DRESSERS
COLLEGE OF PHARMACY	
2 YEARS	D-PHARM
4 YEARS	B-PHRRM
Separate Hostel For Boys & Girls	
9031231082, 7903999411, 60545470	
E-mail: fnsirba@gmail.com	
Website: www.florenceinstirba.com	

न्यूज रील्स

तेलंगाना टनल हादसा: मजदूरों के जिंदा बचने की संभावना कम

नागरकुरुंगल। तेलंगाना के नागरकुरुंगल में निर्माणाधीन श्रीशेलम लॉपट वैक कैनल टनल का एक 22 फॄटरी को ढह गया था। घटना को छठे दिन भी चुके हैं। लॉपट टनल में फेंसे आठ मजदूरों को अब तक नहीं निकला जा सका है। इसके बाद जारी है। शक्ति को साउथ सेंट्रल रेलवे की दौटीमें भी रेस्क्यू के लिए एवं पहुंची। प्राप्त जानकारी के अनुसार किसी भी मजदूर को जीवित लिया जाना संभावना बहुत कम लग रही है। नागरकुरुंगल के एस्पी वैभव गायत्रीकांड ने बताया कि मलबा दूने औं लोहे की छोड़ों की कटिंग का काम लातार जारी है।

पुणे रेप केसः आरोपी पुलिस हिरासत में

पुणे। पुणे में खड़ी बस में 26 साल की लड़की से ऐप के आरोपी रामदास गाड़ को गृहरास को देर रात जिपटार कर लिया गया। इसके बाद शुक्रवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 12 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। क्राइम ब्रांच के ईसीपी निखिल पिंगल ने बताया कि रामदास को शिल्प तहसील के गुनाह जांच से जिपटार किया गया। वह गन्ज के खेत छुपा हुआ था। इस दौरान गांववालों ने हमारी मदद की। गांववालों की बताया कि आपसी जांच में है। तात्पर उसने एक घर से पीक कर पायी और खाना मांगा। इस दौरान लोगों ने उसे पहचान लिया और जानकारी पुलिस को दी।

कोलकाता हाइकोर्ट को पांच नये जज मिले

कोलकाता। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कोलकाता हाइकोर्ट में पांच नये जजों की नियुक्ति को मंजूरी दी दी है। यह फैसला नीतीश कर्जायस्ता ने जारी किया है। नये जजों के रूप में नियुक्त होने वालों में सिमता दास है, उत्तरवार्षीक भित्री, मोहम्मद तलब मसूद सिद्दीकी, कृष्णराज टाकर और ओम नारायण राय के नाम शामिल हैं। फिलहाल कोलकाता हाइकोर्ट में 12 स्वीकृत पदों के मुकाबले के पाँच 43 जज कार्यरत हैं।

उत्तराखण्ड में हिमस्खलन, 57 मजदूर ढहे, 32 का रेस्यू

बढ़ीनाथ हाइवे पर बर्फ हटाने के काम में लगे थे, घार गवाई

आजाद सिपाही संवाददाता

नवी दिल्ली। उत्तराखण्ड के चमोली में शुक्रवार सुबह 7.15 बजे हिमस्खलन की बजह से 57 मजदूर बर्फ में दब गये। मजदूर आठ कंटेनर और एक शेड में थे। घटना बढ़ीनाथ से तीन किलोमीटर दूर चमोली के माणा गांव में हुई। यहां बॉर्टर रोड अंगौंझीजेशन (बीआओ) की टीम चमोली-बढ़ीनाथ हाइवे पर बर्फ हटाने के काम में लगी हुई है। मजदूर

गरीब और होनहार बच्चे होंगे डिजिटल फ्रेंडली: हेमंत

- मुख्यमंत्री ने 28945 संस्कृती प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को सौंपा टैबलेट
- संस्कृती प्राथमिक विद्यालयों को डिजिटल सेवाओं से जोड़ने की दिशा में लिखा गया नया अध्याय

आजाद सिपाही संवाददाता

रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज माना जाना चाहिए एक सेक्टर नहीं बच्चे हैं, जो डिजिटल सेवाओं में भी तेज़ से बदलाव हो रहा है। हर दिन डिजिटल सेवाएं अपग्रेड हो रही हैं। ऐसे में आप चाहें वह ना चाहें, डिजिटल सेवाओं में भी तेज़ से बदलाव हो रहा है।



बच्चों के समग्र विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध

हेमंत सोरेन ने कहा कि आज की शिक्षा व्यापक धैर्य के लिए डिजिटल सेवाओं के प्रभावित होने की बात बार-बार समझ आती है। जिससे लागतों को कमी परेशनिया होती है। ऐसे में सरकार सभी पंचायतों में मोबाइल टावर स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ायेंगे। ताकि डिजिटल सेवाएं से लोगों को जीवन में बदलाव हो सके।

बच्चों का समग्र विकास हमारी सरकारी प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ताकियां जीवन में आपकी मुझी में मोबाइल में बदलाव हो रहा है। आपकी मुझी में मोबाइल में स्मार्ट क्लासर्स चल रहे हैं। हमारे बच्चे अग्रणी डिजिटल फ्रेंडली होनी होती है। तो उनके आगे की राह आसान होनी होती है। इसी बात को ध्यान में रखकर सरकार ने सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे बच्चों को गुणवत्तायुक शिक्षा देना तथा डिजिटल रूप से उन्हें मजबूत करने के लिए आप अपने और आपकी पीढ़ी को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने। जब आप डिजिटल फ्रेंडली होंगे, तभी आपको जीवन में जुट जायी है।

कार्यक्रम का भी ऑनलाइन शुभारंभ किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सरकारी विद्यालयों को डिजिटल सेवाओं पर बोक रहे। राज्य के ने 28945 शिक्षकों को टैबलेट दिया है। आज की साथ सीबीएस और आइसीएस बोर्ड के टॉपर्स को प्रोत्साहन राशि के साथ लैपटॉप और मोबाइल फोन दिया जा रहा है। वर्हां, राज्य सरकार अपने खर्चे पर धैर्य करता है। इसके अलावा अनेक ऐसी योजनाएं हैं, जिनके माध्यम से विद्यार्थियों को कार्यालय के नियंत्रण में जुटाया जाता है। उनके आगे की राह आपकी जीवन में बदलाव होता है।

रिपोर्टिंग कार्य डिजिटल माध्यम से होगा। वर्हां, टैबलेट का प्रयोग बच्चों के पठन-पाठन, शिक्षकों के प्रशिक्षण, अनुश्रुत्य, बायोमिट्रिक उपरिधित दर्जे करने से संबंधित कार्यों की मॉनिटरिंग आसान हो जाय। उनके आगे प्राथमिक विद्यालयों को टैबलेट उपलब्ध कराने के साथ एक नये अध्याय के शुरूआत हो रही है।

बच्चों को प्रत्याहित कर रही है जो उपरिक्त से लेकर सभी कार्यक्रम के नियंत्रण में उपरिधित हो रही है।

सरकार : मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सरकारी विद्यालयों को जीवन में जुटाया जाए।

राज्य के सरकारी विद्यालयों को जीवन में जुटाया जाए।

राज्य के सरकारी विद्यालयों को जीवन में जुटाया जाए।

राज्य के सरकारी विद्यालयों को जीवन में जुटाया जाए।

राज्य के सरकारी विद्यालयों को जीवन में जुटाया जाए।

राज्य के सरकारी विद्यालयों को जीवन में जुटाया जाए।

राज्य के सरकारी विद्यालयों को जीवन में जुटाया जाए।

राज्य के सरकारी विद्यालयों को जीवन में जुटाया जाए।

राज्य के सरकारी विद्यालयों को जीवन में जुटाया जाए।

राज्य के सरकारी विद्यालयों को जीवन में जुटाया जाए।

राज्य के सरकारी विद्यालयों को जीवन में जुटाया जाए।

राज्य के सरकारी विद्यालयों को जीवन में जुटाया जाए।

राज्य के सरकारी विद्यालयों को जीवन में जुटाया जाए।

राज्य के सरकारी विद्यालयों को जीवन में जुटाया जाए।

राज्य के सरकारी विद्यालयों को जीवन में जुटाया जाए।

राज्य के सरकारी विद्यालयों को जीवन में जुटाया जाए।

राज्य के सरकारी विद्यालयों को जीवन में जुटाया जाए।

राज्य के सरकारी विद्यालयों को जीवन में जुटाया जाए।

राज्य के सरकारी विद्यालयों को

बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार से उग्रवादी फरार, मध्य हड़कंप

आजाद सिपाही संचादनाता

रांची। होटेल स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार से एक कैदी फरार हो गया है। शुक्रवार को हुई सामूहिक हाजिरी के बाद जेल प्रशासन के जानकारी मिली कि कैदी फरार हो गया है। जिसके बाद जेल जेल में हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के अनुसार समीर तिक्का उग्रवादी संठन से जुड़ा हुआ है। वह गुरुवार का रहने वाला है। गुमला पुलिस के द्वारा उसे साल 2018 में गिरफतार किया गया था। 2018 से ही समीर रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद था। बताया जा रहा है कि समीर गुरुवार की शाम लाभग 7:00 बजे केंद्रीय



कारागार से फरार हुआ है। कड़ी सुरक्षा के बीच हुआ फरार : रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार की सुरक्षा को लोकर गंभीर सवाल खड़े हो गये हैं। रांची जेल

से समीर तिक्की उर्फ शाकिर तिक्की नाम का कैदी फरार हो गया है। शुक्रवार की सुबह जब कैदियों की शुरुआती शुरू हुई तब जेल प्रशासन को यह जानकारी मिली कि समीर

सरकार चतुर्थवर्गीय पदों पर सीधी नियुक्ति करें: बंधु तिक्की

मुख्यमंत्री से आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम की बायाय कार्यालयों, निगम बोर्ड आदि ने नियमित नियुक्ति करने की अपील



आउटसोर्सिंग कंपनियों पर सख्त निगरानी रखें

श्री तिक्की ने कहा कि वैसे श्रमिकों एवं कर्मचारियों को नियरित पारिश्रमिक या वेतन का भ्रगतान किया जाता है और वैसे लोग किसी से शिकायत करने की स्थिति में भी अपने-आपको असहाय पाते हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि ऐसे कार्यों में कार्यरत अधिकारी आउटसोर्सिंग कंपनियों वैसे अनुबंधित कर्मचारियों एवं श्रमिकों को नियरित राशि की बायाय बहुत कम राशि की भ्रगतान करती हैं। इसके साथ-साथ वैसे कर्मचारियों की अवधियों के अधार पर नियुक्ति से पूर्व उन्हें अवैध रूप से मोटी रकम की भी मांग की जाती है जिसे देने में वे असमर्थ तो होते हैं लेकिन हर महीने रोजगार की लालच में वे जैसे-तैसे उस अवैध मोटी रकम का भ्रगतान आउटसोर्सिंग कंपनी या उसके दलालों, विचालियों आदि को करते हैं याकौंक वैसे अवसर को पाना चाहते हैं।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजे गये एक पत्र में श्री तिक्की ने कहा है कि राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालय के साथ ही अपने अधीनस्थ सभी निगम, बोर्ड आदि में भी चतुर्थवर्गीय पदों पर कर्मचारियों एवं श्रमिकों की सीधी और पूर्ण नियुक्ति के लिए गठन करने के अधार पर उपलब्ध कराये गये अनुबंधित कर्मचारियों को नियरित राशि की बायाय बहुत कम राशि की भ्रगतान करती है। इसके साथ-साथ वैसे कर्मचारियों की अवधियों के अधार पर नियुक्ति से पूर्व उन्हें अवैध रूप से मोटी रकम की भी मांग की जाती है जिसे देने में वे असमर्थ तो होते हैं लेकिन हर महीने रोजगार की लालच में वे जैसे-तैसे उस अवैध मोटी रकम का भ्रगतान आउटसोर्सिंग कंपनी या उसके दलालों, विचालियों आदि को करते हैं याकौंक वैसे अवसर को पाना चाहते हैं।

रांची। पूर्व मंत्री झारखण्ड सरकार की अधिकारीय समिति के सदस्य और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिक्की ने राज्य सरकार से अपील की है कि वह अपने विभिन्न कार्यालयों के साथ ही अपने अधीनस्थ सभी निगम, बोर्ड आदि में भी चतुर्थवर्गीय पदों पर कर्मचारियों एवं श्रमिकों की सीधी और पूर्ण नियुक्ति के लिए गठन करने के अधार पर उपलब्ध कराये गये अनुबंधित कर्मचारियों को नियरित राशि की बायाय बहुत कम राशि की भ्रगतान करती है। इसके साथ-साथ वैसे कर्मचारियों की अवधियों के अधार पर नियुक्ति से पूर्व उन्हें अवैध रूप से मोटी रकम की भी मांग की जाती है जिसे देने में वे असमर्थ तो होते हैं लेकिन हर महीने रोजगार की लालच में वे जैसे-तैसे उस अवैध मोटी रकम का भ्रगतान आउटसोर्सिंग कंपनी या उसके दलालों, विचालियों आदि को करते हैं याकौंक वैसे अवसर को पाना चाहते हैं।

रांची। पूर्व मंत्री झारखण्ड सरकार की अधिकारीय समिति के सदस्य और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिक्की ने राज्य सरकार से अपील की है कि वह अपने विभिन्न कार्यालयों के साथ ही अपने अधीनस्थ सभी निगम, बोर्ड आदि में भी चतुर्थवर्गीय पदों पर कर्मचारियों एवं श्रमिकों की सीधी और पूर्ण नियुक्ति के लिए गठन करने के अधार पर उपलब्ध कराये गये अनुबंधित कर्मचारियों को नियरित राशि की बायाय बहुत कम राशि की भ्रगतान करती है। इसके साथ-साथ वैसे कर्मचारियों की अवधियों के अधार पर नियुक्ति से पूर्व उन्हें अवैध रूप से मोटी रकम की भी मांग की जाती है जिसे देने में वे असमर्थ तो होते हैं लेकिन हर महीने रोजगार की लालच में वे जैसे-तैसे उस अवैध मोटी रकम का भ्रगतान आउटसोर्सिंग कंपनी या उसके दलालों, विचालियों आदि को करते हैं याकौंक वैसे अवसर को पाना चाहते हैं।

रांची। पूर्व मंत्री झारखण्ड सरकार की अधिकारीय समिति के सदस्य और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिक्की ने राज्य सरकार से अपील की है कि वह अपने विभिन्न कार्यालयों के साथ ही अपने अधीनस्थ सभी निगम, बोर्ड आदि में भी चतुर्थवर्गीय पदों पर कर्मचारियों एवं श्रमिकों की सीधी और पूर्ण नियुक्ति के लिए गठन करने के अधार पर उपलब्ध कराये गये अनुबंधित कर्मचारियों को नियरित राशि की बायाय बहुत कम राशि की भ्रगतान करती है। इसके साथ-साथ वैसे कर्मचारियों की अवधियों के अधार पर नियुक्ति से पूर्व उन्हें अवैध रूप से मोटी रकम की भी मांग की जाती है जिसे देने में वे असमर्थ तो होते हैं लेकिन हर महीने रोजगार की लालच में वे जैसे-तैसे उस अवैध मोटी रकम का भ्रगतान आउटसोर्सिंग कंपनी या उसके दलालों, विचालियों आदि को करते हैं याकौंक वैसे अवसर को पाना चाहते हैं।

(क्रम-IV) (नियम 8, समाचारपत्र पंजीकरण (कैंपीज) नियम 1956 के अंतर्गत)

आजाद सिपाही

- प्रकाशन स्थान
- प्रकाशन अवधि
- मुक्त का नाम

: रांची

: दैनिक

: हरिनारायण सिंह

- मुक्त का नाम
- पता

: हाँ

: XXX

: 176 कोकर चौक,

ओल्ड एचबी रोड, रांची-

: 834001

- प्रकाशक का नाम
- राशीयता

: हाँ

: XXX

: 176 कोकर चौक, ओल्ड

एचबी रोड, रांची-

: 834001

- संपादक का नाम
- राशीयता

: हाँ

: XXX

: 176 कोकर चौक, ओल्ड

एचबी रोड, रांची-

: 834001

- उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार पत्र के स्वामी हैं तथा समाचार पत्र के कांसोली के नाम हैं तो यहाँ लिखें

1. हरिनारायण सिंह, 176 कोकर चौक, ओल्ड एचबी रोड, रांची-834001
2. गहुल सिंह, 176 कोकर चौक, ओल्ड एचबी रोड, रांची-834001
3. राकेश सिंह, 176 कोकर चौक, ओल्ड एचबी रोड, रांची-834001

- मैं, हरिनारायण सिंह एतद् द्वारा घोषित करता हूं कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिये गये विवरण सत्य हैं।

द/- राजिनारायण सिंह

प्रकाशक

दिनांक : 28.02.2025

: रांची

: हरिनारायण सिंह

: रांची

: 834001

संपादकीय

ग्रीन कार्ड से कमाई

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वीजा-सिटेजनशिप पॉलिसी पर एक और बड़ी घोषणा करके सबको चौंका दिया है। गोल्ड कार्ड के जरए अमेरिकी विदेशियों को अमेरिका में स्थायी निवास की सुविधा और नागरिकता की गहर मुहैया करने का उनका ऐलान दुनिया भर में तीखी बहस की बजह बन गया है।

44 करोड़ देने होंगे : अमल में आ जाये तो यह स्वीम अमेरिकी विदेशियों को अमेरिकी नागरिकता मुहैया करने का सबसे आसान उपाय साबित हो सकती है। जिस इं-5 कार्यक्रम का विकल्प इसे बताया जा रहा है, उसमें भी अमेरिकी विदेशियों में निवेश का कम से कम 400 अमेरिकियों को रोजगार उपलब्ध करने जैसी शर्तें जुड़ी हैं। मगर इस नई योजना में 50 लाख डॉलर (करोड़ 44 करोड़ रुपये) का भुगतान करने भर से गोल्ड कार्ड मिल जाने की बात है।

आमदानी पर निगाहें : ट्रंप का जोर भी इस नवी योजना से अमेरिका को हानी बाली आमदानी पर ही ज्यादा दिख रहा है। हालांकि कई अन्य देश इस तरह की सुविधा पहले से

दुनिया भर के मुहैया करते हैं, लेकिन वे छोटे-छोटे देश हैं। अमेरिका जैसे देश का ऐसी योजना लेकर आना बड़ी घटना होगी। स्वाभाविक ही, इससे सुरक्षा जैसे सवाल भी जुड़े हैं, क्योंकि ऐसी सुविधा को फायदा उठाने वालों

में अपराधी तत्व भी होते हैं, जो अपने देश के कानून से बचने के लिए ऐसा करते हैं।

टैलंट पर जोर नहीं : भले ट्रंप कह रहे हों कि कंपनियां इस योजना के जरए टैलंट एस्ट्रेंट्स को ज्यादा आसानी से हायर कर पायेंगी, लेकिन यह सफ है कि नवी पॉलिसी का जोर टैलंट से ज्यादा पैसे पर है। ऐसे में इस पॉलिसी का नुकसान उन लोगों को हो सकता है, जो टैलंट की बढ़ीत अमेरिकी को काम कर रहे हैं और बस्तों से ग्रीनकार्ड के इंतजार में हैं। इनमें भारतीयों की अधिक-जैसी संख्या है।

व्यावहारिकता का पहलु : अभी इस घोषणा के साथ कई तरह के किंतु-परंतु जुड़े हैं। अमेरिका में इमिग्रेशन पॉलिसी में किसी भी बड़े बदलाव को कंप्रेस की मुहर चाहिए होती है। यह आशंका भी है कि कंपनियां

नागरिकता संबंधी घोषणा जैसी न हो, जिस पर अदालत ने रोक लगा दी है। इन सबके बावजूद, अमेरिकी राष्ट्रपति की इस घोषणा से यह सवाल ज्यादा स्पष्ट रूप में सामने आया है कि यह सच्चाय पैसा 'स्वर्य' में बिना शर्त एंट्री दिला सकता है।

अभिमत आजाद सिपाही

अमेरिकी साष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पूर्ववर्ती बाइडेन प्रशासन पर आरोप लगाया कि उसने भारत में चुनाव प्रभावित करने के लिए 21 मिलियन डालर खर्च किये। ट्रंप ने सवाल उठाया कि यह इसके जरूर बाइडेन किसी और को जिताने की कोशिश कर रहे थे। ट्रंप का यह बयान उस समय आया, जब अमेरिकी सरकारी दस्तावेज द्वारा भारत में मतदान प्रतिशत हेतु अमेरिकी वित्तपोषण का भवित्व बन गया।

फरवरी को अपनी एक रिपोर्ट में यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (यूएस-एड) द्वारा भारत में तत्वावधान प्रतिशत हेतु अमेरिकी वित्तपोषण का भवित्व बन गया।

भीतरी और बाहरी दुर्घटनों से सावधान!

बलबीर पुंज

अनादिकाल से भारत एक महान आध्यात्मिक शक्ति रहा है। 250 वर्ष पहले तक विषय की सबसे मजबूत अर्थिक शक्ति थी। लगातार संघर्ष के बाद भी हम लगभग 600 वर्षों इस्लाम, तो 200 साल अंग्रेजों के अधीन रहे। यह तब हुआ, जब हम स्वीर्ण और किसी भी साधन में कम नहीं थे। शताब्दियों तक चली इस पतंत्रता का एक बड़ा कारण वह वर्ग रहा, जो अपने निहित स्वार्थ के लिए किसी न किसी शायु से जा मिला और हम कमज़ोर होते गए। यह दुखद इतिहास में हमने कुछ सीधी? शायद नहीं। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने के नाम पर भारत में 182 करोड़ के भारी-भरकम अमेरिकी वित्तपोषण का खुलासा करते हुए इसे बंद कर दिया। यह पर्फॉरमेंस इस बात को रेखांकित करता है कि बढ़ते भारत पर लगाम लगाने के लिए विदेशी शक्तियों किस तरह बेसब्र हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पूर्ववर्ती बाइडेन प्रशासन पर आरोप लगाया कि उसने भारत में चुनाव प्रभावित करने के लिए 21 मिलियन डालर खर्च किये।

उठाया कि क्या इसके जरए बाइडेन किसी और को जिताने के लिए देश छोड़कर भागना पड़ा था,

बाइडेन किसी और को जिताने की कोशिश कर रहे थे।

ट्रंप का यह बयान उस समय आया, जब अमेरिकी सरकारी दबावता द्वारा विभाग ने 16 फरवरी को अपनी एक

रिपोर्ट में यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी का अपराधी देश पर जाना चाहिए होती है।

इसी विवेदी के बाद अमेरि�की वित्तपोषण को अपराधी देश पर जाना चाहिए होती है।

देवलपमेंट (यूएस-एड) द्वारा

भारत में मतदान प्रतिशत हेतु अमेरिकी

वित्तपोषण का भांडाफोड़ किया था। इसी

रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि

बांगलादेश में राजनीतिक गतिविधि

करने के नाम पर भी 29 मिलियन डालर

को

